आर. एन. आई. नं. UPHIN/2010/32566 डाक. पंजीयन. संख्या– SSP/LW/NP-311

# अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 16 अंक : 46 लखनऊ, शनिवार 14 मार्च 2026 से 20 मार्च 2026 तक पृष्ठ–8 मूल्य : एक रुपया

## प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन असमः चुनाव से पहले रुपये ४५७० करोड़ की सौगात, नई रेल को दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ४,५७० करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया और असम के कोकराझार और उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में संपर्क सुधारने के उद्देश्य से तीन नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये तीन ट्रेनें हैंः कामाख्या–चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, गुवाहाटी–न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस और नारंगी–अगरतला एक्सप्रेस। विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री दो दिवसीय असम दौरे पर हैं। खराब मौसम के कारण कोकराझार न जा पाने के कारण उन्होंने गुवाहाटी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूमि पूजन किया और ४,५७० करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कामाख्या– चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस उत्तर–पूर्व और दक्षिण भारत के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जबकि गुवाहाटी–न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस असम और पश्चिम बंगाल के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी और नारंगी–अगरतला एक्सप्रेस असम और त्रिपुरा के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगी, जिससे यात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों के लिए अंतर–राज्यीय यात्रा सुगम होगी। ये परियोजनाएं असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में स्थित कोकराझार जिले में यातायात की

भीड़ को कम करने में मदद करेंगी और कनेक्टिविटी, पर्यटन, कृषि तक पहुंच, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और ग्रामीण गतिशीलता में सुधार करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कोकराझार जिले के बाशबारी में आवधिक मरम्मत (पीओएच) कार्यशाला की आधारशिला भी रखी। यह कार्यशाला रेलवे रखरखाव अवसंरचना को मजबूत करेगी, परिचालन दक्षता बढ़ाएगी और क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ३,२०० करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली प्रमुख सड़क अवसंरचना परियोजना, असम माला ३.० का वर्चुअल भूमि पूजन भी किया। इस योजना के तहत, अंतर–राज्यीय संपर्क में सुधार और राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए असम भर में ६०० किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) क्षेत्र में लगभग १,१०० करोड़ रुपये के निवेश से निर्मित छह सड़क अवसंरचना परियोजनाओं, जिनमें चार फ्लाईओवर और दो पुल शामिल हैं, का भी भूमि पूजन किया। १४ मार्च को, प्रधानमंत्री सिलचर में लगभग २३,५५० करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। असम में विधानसभा चुनाव अगले महीने होने की उम्मीद है, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की तैयारी कर रही है।

## यूपी में गोकशी-गोतस्करी पर योगी सरकार सख्त : विशेष अभियान के तहत ३५ हजार आरोपियों को भेजा गया जेल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गोकशी, गोतस्करी और अवैध पशु वध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत अब तक प्रदेश भर में गोकशी के १४,१८२ मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें ३५,६२४ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, गोकशी के मामलों में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ सामान्य मुकदमों के साथ–साथ कड़े कानूनों के तहत भी कार्रवाई की गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ३५,६२४ आरोपियों में से १३,७६३ के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जबकि १७८ आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाया गया। इसके अलावा १४,३०५ मामलों में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कठोर कार्रवाई की गई है। सरकार की इस सख्ती से गोकशी और गोतस्करी से जुड़े संगठित गिरोहों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिली है। पुलिस और प्रशासन ने कई जिलों में सक्रिय नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त किया है। गोकशी से जुड़े अपराधियों पर केवल कानूनी ही नहीं बल्कि आर्थिक कार्रवाई भी की गई है। गैंगस्टर एक्ट की ६ धारा १४(१) के तहत कार्रवाई करते हुए अब तक लगभग ८३ करोड़ ३२ लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई

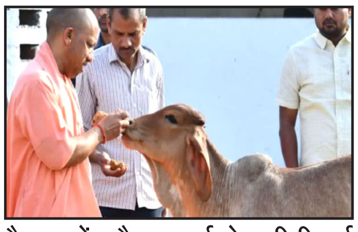

है। इसमें अवैध कमाई से खरीदी गई जमीन, वाहन और अन्य संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं। सरकार का उद्देश्य अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त कर ऐसे संगठित गिरोहों की आर्थिक ताकत को कमजोर करना है, ताकि भविष्य में इस प्रकार के अपराधों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। प्रदेश में गोकशी और गोतस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस की विशेष टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों द्वारा खुफिया तंत्र को सक्रिय करते हुए जिलास्तरीय टास्क फोर्स के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और रात के समय पुलिस गश्त भी बढ़ाई गई है। इसके साथ ही पशु परिवहन से जुड़े मामलों की भी विशेष निगरानी की जा रही है। कई जिलों में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। वर्ष २०२० में लागू उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन आफ काउ स्लाटर अध्यादेश २०२० के तहत गोकशी के मामलों में कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। गोहत्या के मामलों में १० वर्ष तक कठोर कारावास और से ५ लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। इसके अलावा गोवंश के अंगभंग करने पर ७ वर्ष तक की सजा और ३ लाख रुपये तक जुर्माना देना होगा। सरकार का दावा है कि सख्त कानून, विशेष अभियान और आर्थिक कार्रवाई जैसे कदमों के कारण प्रदेश में अवैध पशु वध और गोतस्करी से जुड़े मामलों में काफी कमी आई है और संगठित गिरोहों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगा है।

## योगी सरकार ने लखनऊ को बनाया वर्ल्डक्लास सिटीः राजनाथ सिंह

लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को ग्रीन क रिडोर परियोजना के दूसरे चरण के लोकार्पण के अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लखनऊ तेजी से विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास अब केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के जीवन में दिखाई दे रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आईआईएम रोड से आउटर रिंग रोड तक लगभग २८ किलोमीटर लंबे ग्रीन क रिडोर से करीब १५ लाख लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी और शहर में जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के निर्माण के दौरान पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा गया और रास्ते में आने वाले १५० से अधिक पेड़ों को काटने के बजाय दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस परियोजना में सेना की जमीन का भी उपयोग हुआ है और सिविल व रक्षा संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय से इसे पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि जब सिविल और डिफेंस मिलकर काम करते हैं तो विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लखनऊ की तहजीब के साथ–साथ यहां के विकास की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। विदेशों में रहने वाले भारतीय जब लखनऊ आते हैं तो यहां के विकास को देखकर प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि यूनेस्को द्वारा लखनऊ को 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोन मी' का दर्जा मिलना पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश

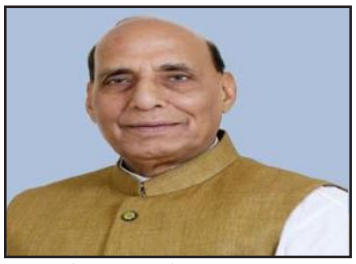

आज देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। डिफेंस क रिडोर और ब्रह्मोस एयरोस्पेस परियोजनाओं से प्रदेश रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सैन्य शक्ति का प्रतीक है और इससे आतंकवाद के खिलाफ देश को मजबूती मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाल के सिंगापुर और जापान दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि योगी जी अपने गेरुए वस्त्र में ही वहां गए और अपनी सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत किया। विदेशों से मिले अनुभव और तकनीकी सहयोग से लखनऊ के शहरी विकास को नई गति मिलेगी।

## बरेली को मिला सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में पहला स्थान

लखनऊ। प्रदेश में जनसमस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने के लिए लागू मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की फरवरी रैंकिंग में बरेली जिले ने पहला स्थान हासिल किया है। जनशिकायतों के समयबद्ध निस्तारण और बेहतर फीडबैक के आधार पर बरेली ने १० में से ६.६५ अंक प्राप्त कर पूरे प्रदेश में शीर्ष स्थान पाया। सीएम डैशबोर्ड पर जिलों का मूल्यांकन जनशिकायतों के समाधान, शिकायतों पर कार्रवाई, फीडबैक की गुणवत्ता और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे प्रमुख मानकों के आधार पर किया जाता है। इन सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए बरेली प्रशासन ने यह उपलब्धि हासिल की है। फरवरी रैंकिंग में शाहजहांपुर ने ६.५३ अंक के साथ दूसरा और मैनपुरी ने ६.५० अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रशासनिक स्तर पर शिकायतों के प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण और सकारात्मक फीडबैक ने इन जिलों की रैंकिंग मजबूत की है। रैंकिंग में अन्य जिलों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। लखीमपुर खीरी ने ६.४६ अंक के साथ चौथा, जालौन ने ६.४५ अंक के साथ पांचवां और रामपुर ने ६.३६ अंक के साथ छठा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा हमीरपुर सातवें, बाराबंकी आठवें, पीलीभीत नौवें और श्रावस्ती दसवें स्थान पर रहे।

# सम्पादकीय

## युद्ध की आहट या नीतिगत चूक? गैस संकट के लिए किसकी तय होगी जवाबदेही?

रसोई गैस के लिए हाहाकार मच गया है। जगह–जगह से सिलिंडर भरवाने के लिए गैस एजेंसियों के सामने लंबी कतारों की खबरें मिल रही हैं। ये हाल तब है, जबकि सरकार ने एलपीजी की ८०–८५ फीसदी सप्लाई औद्योगिक क्षेत्र से घरेलू उपयोग के लिए भेजने का निर्णय लिया है। कॉमर्शियल उपयोग के लिए गैस की सप्लाई काफी हद तक बाधित हो चुकी है। गौरतलब है कि अभी संकट के शुरुआती दिन हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध लंबा खिंचा (जिसकी पूरी संभावना है) और होरमुज जलडमरुमध्य का मार्ग बंद रहा, तो आने वाले दिनों में नोटबंदी या कोरोना काल जैसे परिमाण के संकट का सामना देश को करना पड़ सकता है। अब यह सामने आया है कि चूंकि गैस का भंडारण मंहगा पड़ता है, इसलिए भारत ने खुद को लगातार सप्लाई पर ही निर्भर बनाए रखा। अब चूंकि मुश्किल आ खड़ी हुई है, तो सरकार आपातकालीन निर्णय लेने को मजूबर है। उसने ऐसे लिए हैं, जिनसे घरेल उपभोक्ताओं को अधिकतम राहत मिल सके। यह सही, मगर समस्याग्रस्त प्राथमिकता है। आखिर श्रमिक वर्ग के लोग फेक्टरियों या कार्यस्थलों पर कैंटीन या ढाबों में भोजन करते हैं। लाइन होटल ट्रक एवं बस ड्राइवरों और अन्य लंबी दूरी के यात्रियों के खाना खाने की जगहें हैं। फिर अनगिनत लोग रोज कामकाज के सिलसिले में यात्राओं पर जाते हैं, जो रेस्तरां या होटलों में ही भोजन करते हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि अनेक शहरों से रेस्तरां और होटलों में मेनू की कटौती हो रही है और कुछ रोज में उनके बंद हो जाने की चेतावनी दी गई है। रेस्तरां और क्लाउड किचन पर लाखों कर्मचारी एवं होम फूड डिलीवरी से जुड़े गिग वर्कर निर्भर हैं। उधर औद्योगिक गैस की कटौती से कल–कारखाने बंद हुए, तो उसका असर लाखों नौकरीशुदा लोगों पर पड़ेगा। उत्पादन, वितरण, एवं उपभोग में गिरावट से अर्थव्यवस्था पर होने वाला दूरगामी असर अलग है। तो कुल मिलाकर देश एक बड़ी मुश्किल में फंसता नजर आ रहा है। इसके मद्देनजर क्या यह कहना काफी होगा कि युद्ध होता है, तो दिक्कत होती है? या एहतियाती कदम ना उठाने के लिए किसी की जवाबदेही तय होगी?

## गैस एजेंसी व मस्जिदों का सुरक्षा निरीक्षण किया

गोला गोकर्णनाथ खीरी। गोला क्षेत्र में कानून व्यवस्था को ष्टिगत रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दिया। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी गोला रमेश कुमार तिवारी, थाना प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह तथा नानक चौकी इंचार्ज योगेश कुमार ने मय पुलिस बल के साथ क्षेत्र में गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए कर्मचारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। साथ ही अलविदा जुम्मा की नमाज को लेकर क्षेत्र की मस्जिदों का भी निरीक्षण किया गया। पुलिस अधिकारियों ने मस्जिदों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में नमाज संपन्न कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।

# उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी

लखनऊ। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, १६७५ में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (अठारहवां संशोधन) नियमावली, २०२६ लागू की जाएगी। इसके तहत भर्ती, कोटा और चयन प्रक्रिया से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। संशोधन के अनुसार भर्ती के स्रोत से जुड़े नियम–५, कोटा से संबंधित नियम–६, चयन प्रक्रिया से जुड़े नियम–१८, पदोन्नति से संबंधित नियम–२०, नियुक्ति से जुड़े नियम–२२ और परिशिष्ट–१ में बदलाव किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत सिविल जज (सीनियर डिवीजन) से पदोन्नति का कोटा ६५ प्रतिशत से घटाकर ५० प्रतिशत कर दिया गया है। यह पदोन्नति श्रेष्ठता और वरिष्ठता के आधार पर तथा उपयुक्तता परीक्षा पास करने वाले अधिकारियों को दी जाएगी। वहीं, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के जरिए पदोन्नति का कोटा १० प्रतिशत से बढ़ाकर २५ प्रतिशत कर दिया गया है। इसमें वही सिविल जज शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने उस पद पर कम से कम तीन साल की सेवा और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में कम से कम सात साल की सेवा पूरी की हो। इसके अलावा अधिवक्ताओं (बार) से सीधी भर्ती का कोटा पहले की तरह २५ प्रतिशत ही रहेगा। कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर किया गया। इसके तहत बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत जनपद बांदा में २० हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के नए डेयरी प्लांट की स्थापना और झांसी में पहले से स्थापित १० हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट का विस्तार कर उसे ३० हजार लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इन परियोजनाओं के सिविल और मैकेनिकल कार्य टर्न–की आधार पर कराने के लिए इंडियन डेयरी मशीनरी कंपनी लि. को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। कैबिनेट ने इस कंपनी को नियमानुसार सेंटेज चार्ज देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिसका व्यय राज्य सरकार अपने स्रोतों से वहन करेगी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है और प्रदेश में दुग्ध उत्पादों की

मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बुंदेलखंड क्षेत्र में डेयरी प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने से दुग्ध उत्पादकों को उनके दूध का बेहतर और बाजार आधारित मूल्य मिल सकेगा। इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में दूध के खराब होने की समस्या कम होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और बुंदेलखंड में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही यह पहल प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में भी सहायक मानी जा रही है। कैबिनेट बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस निर्माण इकाई स्थापित करने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत टीआई मेडिकल्स प्रा. लि. को भूमि सब्सिडी प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। कंपनी द्वारा गौतमबुद्ध नगर स्थित यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथ रिटी (यीडा) के मेडिकल डिवाइस पार्क क्षेत्र में ४.४८ हेक्टेयर भूमि पर करीब २१५.२० करोड़ रुपए के निवेश से चिकित्सा उपकरण निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश की एफडीआई, एफसीआई और फॉर्च्यून इंडिया–५०० निवेश प्रोत्साहन नीति–२०२३ के तहत प्रस्तावित है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, कंपनी को अनुमन्य सब्सिडी के तहत १४.७७ करोड़ रुपए की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। यह राशि केंद्र सरकार की मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के अंतर्गत पहले से प्राप्त सब्सिडी को समायोजित करने के बाद दी जाएगी। इस निवेश से प्रदेश में मेडिकल डिवाइस निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। यह पहल राज्य को निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगी। इस परियोजना से संबंधित प्रस्ताव पर पहले विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया था। उत्तर प्रदेश की एफडीआई, एफसीआई एवं फ र्च्यून ग्लोबल ५००/फॉर्च्यून इंडिया ५०० निवेश प्रोत्साहन नीति–२०२३ के तहत प्राधिंत समिति की ५ जुलाई २०२४ को हुई बैठक में परियोजना को मंजूरी दी गई थी और कंपनी को २२ जुलाई २०२४ को पात्रता प्रमाणपत्र भी जारी किया गया। बाद में १५ मई २०२५ को हुई इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में सब्सिडी से जुड़े बिंदुओं पर विचार किया गया। मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के अंतर्गत कंपनी को पहले से केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी प्राप्त हो चुकी है। इसी आधार पर एफडीआई नीति के तहत अनुमन्य कुल सब्सिडी ४१.५२ करोड़ रुपए में से पहले प्राप्त सब्सिडी घटाकर शेष १४.७७ करोड़ रुपए की राशि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) द्वारा कंपनी को प्रतिपूर्ति के रूप में देने का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे अब मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है।

# जेवर एयरपोर्ट का पहला चरण जल्द होगा शुरू

लखनऊ। गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेजी से संचालन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पहले चरण का लगभग ६५ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष कार्य १० नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। पहले चरण में एयरपोर्ट को एक रनवे के साथ संचालित किया जाएगा। इसकी सालाना यात्री क्षमता करीब १ करोड़ २० लाख होगी और प्रतिदिन औसतन करीब १५० उड़ानों के संचालन का अनुमान है। अधिकारियों के अनुसार, जैसे ही यात्रियों की संख्या एक करोड़ के आंकड़े को पार करेगी, एयरपोर्ट पर दूसरे

रनवे के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दो रनवे के साथ यह एयरपोर्ट करीब ७ करोड़ यात्रियों को सेवा देने में सक्षम होगा। परियोजना के पहले चरण में लगभग ३,३०० एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे हिस्से का लोकार्पण किया जाएगा। एयरपोर्ट के लिए अब तक ६,७०० एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है, जबकि शेष ५,१०० एकड़ भूमि अगले तीन महीनों में अधिग्रहित करने की योजना है। भूमि खरीद पर करीब ५,००० करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, वहीं निर्माण कार्य पर लगभग ७००० करोड़ रुपए की लागत आ रही है। सरकार की योजना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश के सबसे बड़े और आधुनिक हवाई अड्डों में से एक के रूप में विकसित किया जाए। परियोजना पूरी होने के बाद यहां कुल पांच रनवे होंगे और एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल लगभग ११,७५० एकड़ तक पहुंच जाएगा। अंतिम रूप से तैयार होने पर इसकी सालाना यात्री क्षमता करीब ३० करोड़ होने का अनुमान है, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल हो सकता है। एयरपोर्ट के निर्माण से क्षेत्र में आर्थिक और औद्योगिक विकास को भी बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके आसपास ल जिस्टिक्स, पर्यटन, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी और बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ते यात्री दबाव को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। साथ ही, यह परियोजना दिल्ली–एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र के रूप में उभरेगी और प्रदेश को वैश्विक निवेश व व्यापार के नक्शे पर और मजबूती से स्थापित करेगी।

# प्रदेश में गैस की कमी नहीं तो नेता जनता को दिलाएं सिलेंडर: अखिलेश यादव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जारी रसोई गैस सिलेंडर के संकट के बीच समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में रसोई गैस की किल्लत को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा के नेता यह दावा कर रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है, तो फिर उनके मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर गैस एजेंसियों से लोगों को सिलेंडर क्यों नहीं दिलवा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाले भाजपा नेता इस संकट के समय भूमिगत क्यों हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को अपने ठिकानों से बाहर निकलकर जनता के बीच जाना चाहिए और लोगों को गैस उपलब्ध कराने में मदद करनी चाहिए। उन्होने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अब जनता भाजपा

नेताओं के घरों, कार्यालयों या प्रतिष्ठानों का घेराव करे। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी किसी चीज की किल्लत बढ़ती है, भाजपा उसे नकारने लगती है और वास्तविक समस्या से ध्यान हटाने की कोशिश करती है। सपा प्रमुख ने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन गैस की कमी से लेकर आज रसोई गैस और खाद की किल्लत तक, भाजपा की यही प्रवृत्ति रही है कि संकट को स्वीकार करने के बजाय उसे झुठलाया जाए। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा आपदा के समय भी कालाबाजारी को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियां पैदा करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की गलतियों का खामियाजा आम जनता को क्यों भुगतना पड़े। उन्होंने कहा कि अगर सत्ताधारी दल और उससे जुड़े संगठन सेवा का दावा करते हैं तो उन्हें भूख से परेशान लोगों के लिए मुफ्त भोजनालय चलाने चाहिए, अन्यथा जनता के सामने आने से बचना चाहिए।

# उत्तर प्रदेश सरकार ने तेज की एलपीजी वितरण निगरानी, कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पश्चिम एशिया में तनाव के कारण फैली अफरा–तफरी के दौरान जमाखोरी के मद्देनजर जिलों में एलपीजी और ईंधन वितरण की निगरानी तेज कर दी है और जमाखोरी व कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने बार–बार भरोसा दिलाया है कि राज्य में एलपीजी या पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कन्नौज जिले में शुक्रवार को गुरसहायगंज कस्बे में कालाबाजारी के आरोपों के बाद छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर और बुकिंग रिकॉर्ड जब्त किए। छिबरामऊ के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने बताया कि बगिया इलाके के एक घर में एलपीजी सिलेंडरों के अवैध भंडारण व बिक्री की सूचना मिली थी। द्विवेदी ने कहा, ‘सूचना मिली थी कि परिसर में कालाबाजारी के लिए १५० से अधिक सिलेंडर जमा किए जा रहे थे। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई।’ छापेमारी के दौरान, अधिकारियों ने घर के एक कमरे से ११ खाली सिलेंडर और एक भरा हुआ सिलेंडर बरामद किया, साथ ही ११३ गैस बुकिंग पुस्तिका भी मिलीं। एसडीएम ने कहा, ‘प्रारंभिक जांच के दौरान गैस एजेंसी के संचालक और कुछ

कर्मचारियों के बीच मिलीभगत का संकेत मिला है। सिलेंडर और बुकिंग बुक जब्त कर ली गई हैं और जांच शुरू कर दी गई है।ß अधिकारियों ने बताया कि इस बीच, देवरिया जिले में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों ने घोषणा की है कि शनिवार से एलपीजी सिलेंडरों की होम डिलीवरी पूरी तरह से फिर से शुरू हो जाएगी। मित्तल ने कहा कि सिलेंडरों का वितरण ष्पहले आओ, पहले पाओ' के सिद्धांत के अनुसार होगा। उन्होंने कहा, षजिन उपभोक्ताओं ने पहले बुकिंग कराई है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और सभी बुकिंग क्रमानुसार पूरी की जाएंगी।’ उन्होंने लोगों से धैर्य रखने और अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया। मित्तल ने कहा, ‘कालाबाजारी या अधिक कीमत पर बिक्री के मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।’ लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग ने एलपीजी एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे सिलेंडरों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करें और उपभोक्ताओं को असुविधा न हो। नागपाल ने कहा कि जिले में एलपीजी सिलेंडरों का पर्याप्त भंडार है और लोगों से अपील की कि वे घबराकर खरीदारी न करें। जिला आपूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने भी कहा कि जिले में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति श्रृंखला सुचारू रूप से चल रही है।

## पलिया में ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार ३५ हजार की स्मैक बरामद

लखीमपुर खीरी। पलिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को ब्राउन शुगर (स्मैक) के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से लगभग १०.१० ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत ३५ हजार रुपये बताई जा रही है।पुलिस अधीक्षक खीरी डॉ. ख्याति गर्ग के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन पर रोक लगाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी पलिया के मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी के नेतृत्व में पलिया पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान विशाल पुत्र घनश्याम (लगभग २५ वर्ष) के रूप में हुई है। वह पलिया कस्बे के मोहल्ला किसान द्वितीय, जिला खीरी का निवासी है।पुलिस ने विशाल के खिलाफ मु०अ०सं० ७५/२०२६ धारा ८/२१ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया।पुलिस के अनुसार, आरोपी विशाल का आपराधिक इतिहास

भी रहा है। उसके खिलाफ भीरा, कोतवाली सदर, पलिया और मझगई थानों में चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगेस्टर एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।

## पीएम किसान सम्मान निधि जारी रू यूपी के किसानों को मिले ४३३५ करोड़ रुपये

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के दौरे के दौरान गुवाहाटी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की २२वीं किस्त जारी कर दी। इस किस्त के तहत देशभर के ६.३२ करोड़ किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सम्मान निधि की राशि भेजी गई। इसमें उत्तर प्रदेश के २.१५ करोड़ से अधिक किसानों को भी बड़ा लाभ मिला है। प्रदेश के किसानों के खातों में सीधे ४३३५.११ करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक लाभ पाने वाला राज्य बना हुआ है। २२वीं किस्त जारी होने से पहले तक प्रदेश के किसानों को २१ किस्तों में कुल ६४,६६८.५८ करोड़ रुपये की सहायता मिल चुकी थी। अब नई किस्त के ४३३५.११ करोड़ रुपये जुड़ने के बाद यह राशि बढ़कर ६९,००३.६९ करोड़ रुपये हो गई है। देश के कुल लाभार्थियों में लगभग २३ प्रतिशत किसान उत्तर प्रदेश से हैं, जो इस योजना में प्रदेश की बड़ी भागीदारी को दर्शाता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवार के एक सदस्य को प्रतिवर्ष ६,००० रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में दो–दो हजार रुपये के रूप में सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। प्रधानमंत्री ने २४ फरवरी २०१९ को गोरखपुर से इस योजना की शुरुआत की थी। तब से यह योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक सहारा बन चुकी है और लगातार अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ

मिल रहा है। इस बीच, प्रधानमंत्री द्वारा २२वीं किस्त जारी किए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा कि कृषक–कल्याण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता एक बार फिर करोड़ों अन्नदाताओं के जीवन में विश्वास और संबल लेकर आई है। उन्होंने कहा कि इस किस्त के तहत ६.३२ करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में १८,६४० करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि सीधे पहुंची है, जिसमें उत्तर प्रदेश के २.१५ करोड़ से अधिक किसान भी लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार यह पहल किसानों के जीवन को सुगम बनाने और खेती को नई शक्ति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

# बसपा के कोर वोटरों में सेंध लगाने में क्या सफल हो पाएगी कांग्रेस

लखनऊ। कांग्रेस ने पहली बार बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती को सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया है तो इसके पीछे सियासी फायदे की गणित भी साफ दिखाई दे रहा है। अगले साल विधान सभा चुनाव हैं। बसपा का कोर वोटर समझे जाने वाले दलित वर्ग के वोटरों की संख्या यूपी में खासी प्रभावी है। करीब १०० विधान सभा सीटों पर दलित वर्ग के वोट खासे निर्णायक स्थिति में हैं, जिसमें ८४ सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। इन पर कांग्रेस की सीधी नजर है। बड़ा सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस इस आयोजन के जरिए बसपा के कोर वोटरों में सेंध लगाने में कितनी सफल होगी। बसपा संस्थापक कांशीराम और मायावती ने खासा संघर्ष कर दलित वर्ग को पार्टी से जोड़ा था। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक प्रदेश में करीब १६ फीसदी वोट दलित वर्ग का है। जिसमें जाटव करीब १२ फीसदी और गैर जाटव सात फीसदी के करीब है। इन १६ फीसदी वोटरों के दम पर ही मायावती चार बार सूबे की मुख्यमंत्री रहीं। हालांकि इसमें सोशल इंजीनियरिंग का भी बड़ा हाथ रहा। लेकिन कोर वोटर साथ होने के कारण ही अन्य समाज के लोग बसपा के साथ आए। लेकिन वर्ष २०१२ में बसपा के हाथ से सत्ता खिसकी तो अभी तक ग्राफ गिरता ही जा रहा है। हालत यह रहे कि वर्ष २०२२ के चुनाव में बसपा के महज एक विधायक ही निर्वाचित हो पाए। बसपा की इस गिरावट का फायदा वर्ष २०२४ के लोकसभा चुनाव में सपा–कांग्रेस गठबंधन को कुछ हद तक मिला। तभी से कांग्रेस और सपा ने दलित वर्ग पर डोरे डालने शुरू कर दिए। उधर एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती अपने पुराने फार्म में लौटने की कवायद में हैं। बीते नौ अक्टूबर–२५ को संस्थापक कांशीराम की पुण्य तिथि पर लखनऊ में जिस तरह से लाखों लोगों की भीड़ जुटी, इससे संकेत हैं कि कोर वोटर एक बार फिर बसपा की तरफ लौट रहा है। साथ ही मायावती की भी सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। इसके चलते कांग्रेस दलित वोटरों का कितना हिस्सा अपने पाले में कर पाती है। यह भविष्य ही बताएगा।

# अगर नेहरु जीवित होते तो कांशीराम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होतेः राहुल गांधी

लखनऊ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि केवल 'राहुल गांधी जिंदाबाद' के नारे लगाने से कोई फायदा नहीं

होता। बदलाव तब आता है जब व्यक्ति यह ठान ले कि जो गलत हो रहा है उसे वह स्वीकार नहीं करेगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भाषण देने से पहले वह सोच रहे थे कि बी आर अंबेडकर शिक्षा और संगठन की बात करते थे। आज लोग कांशी राम को याद करते हैं, लेकिन समाज को १५ और ८५ में बांट दिया गया है। उन्होने आरोप लगाया कि इसका फायदा केवल १५ प्रतिशत लोगों को मिल रहा है, जबकि बाकी ५० प्रतिशत समाज को अलग–अलग कर दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरु आज जीवित होते तो कांशीराम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम एपस्टीन फाइल में बताया जा रहा है और उनकी बेटी की कंपनी में ज र्ज सोरोस की फंडिंग का भी उल्लेख किया गया है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि जब कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था, तब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सीटें घटकर ३६ रह गई थीं, जबकि महागठबंधन ने ४३ सीटों पर जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि यही सफलता महागठबंधन २०२७ के विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहता है।

# टीआरसी लॉ कॉलेज में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारम्भ

बाराबंकी। सतरिख स्थित टीआरसी लॉ कॉलेज में 'पारम्परिक ज्ञान एवं सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भारतीय ज्ञान प्रणाली की भूमिका' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारम्भ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डा. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डा.) बिजेन्द्र सिंह, प्रो. (डा.) बी.पी. सिंह, डा. जयशंकर प्रसाद पाण्डेय, डा. मंजुल त्रिवेदी, शासी निकाय अध्यक्ष डा. सुजीत चतुर्वेदी तथा प्राचार्य डा. अश्वनी कुमार गुप्ता ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर किया। प्राचार्य डा. अश्वनी कुमार गुप्ता ने संगोष्ठी की प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए भारतीय ज्ञान परम्परा के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता डा. मंजुल त्रिवेदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परम्परा की प्रासंगिकता बताते हुए समावेशी विकास की अवधारणा पर जोर दिया। मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. (डा.) बिजेन्द्र सिंह ने कहा कि शिक्षा और समाज एक–दूसरे के पूरक हैं तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। डा. जयशंकर प्रसाद पाण्डेय ने भारतीय और पाश्चात्य ज्ञान प्रणालियों की तुलना करते हुए गुरुकुल परम्परा तथा तक्षशिला

व नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों के योगदान को रेखांकित किया। प्रो. बी.पी. सिंह ने कहा कि शिक्षा मनुष्य में नैतिक मूल्यों और ईमानदारी का विकास करती है, जो भारतीय ज्ञान परम्परा का मूल आधार है। शासी निकाय अध्यक्ष डा. सुजीत चतुर्वेदी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। संगोष्ठी के अंतर्गत दो तकनीकी सत्र आयोजित हुए। प्रथम सत्र की अध्यक्षता प्रो. बी.पी. सिंह और डा. शिव बहादुर तिवारी ने की, जिसमें १६ प्रतिभागियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। द्वितीय सत्र की अध्यक्षता डा. संजय बरनवाल और डा. आलोक पाण्डेय ने की, जिसमें १० प्रतिभागियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। इस अवसर पर परास्नातक विभागाध्यक्ष डा. अविनाश मिश्रा, डा. शिव शरन, डा. दीपमाला श्रीवास्तव, डा. वीर विक्रम सिंह, डा. नवीन कुमार सिंह, डा. इन्द्र दमन तिवारी, डा. मंजय कुमार यादव, डा. अमजद अंसारी, डा. प्रमोद कुमार पाण्डेय, डा. धर्मेन्द्र कुमार, प्रवक्ता अंकित मिश्रा, रोहिणी त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे।

# संविधान के साथ सामाजिक मूल्यों व परंपराओं की भूमिका महत्वपूर्णः प्रो. अमर पाल सिंह

बाराबंकी। श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज द्वारा शुक्रवार को 'एक्सपर्ट टॉक १.०' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एक्सपर्ट लीगल लुमिनरी के रूप में डॉ.

राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रो. (डॉ .) अमर पाल सिंह मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय के चांसलर इंजी. पंकज अग्रवाल, प्रो–चांसलर इंजी. पूजा अग्रवाल, कुलपति प्रो. (डॉ.) विजय तिवारी और कुलसचिव प्रो. (डॉ.) हेमेंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का विषय संवैधानिक दर्शन और सुशासन रहा। अपने व्याख्यान में प्रो. अमर पाल सिंह ने सुशासन की अवधारणा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनभागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने मेटा–संविधान की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा कि संविधान के साथ–साथ सामाजिक मूल्यों, परंपराओं और संवैधानिक संसेति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के निदेशक प्रो. (डॉ.) नरेंद्र सिंह बहादुर ने की, जबकि संचालन गेस्ट लेक्चर कमेटी के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने कमेटी सदस्य आस्था मिश्रा, आनंद कुमार और कुलदीप कुमार यादव के साथ किया। इस अवसर पर डॉ. प्रकाश चंद्र मिश्रा, डॉ. शशांक शेखर, डॉ. महेंद्र कुमार, डॉ. श्रुति शर्मा, डॉ. विवेक मिश्रा सहित सभी संकाय सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम मुख्य रूप से विधि संकाय के सभी वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया।

# यूपी में आज से स्मार्ट मीटरिंग व्यवस्था लागू, माइनस बैलेंस पर कट सकती है बिजली

लखनऊ। प्रदेश में शुक्रवार से स्मार्ट मीटरिंग व्यवस्था लागू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सभी उपभोक्ताओं से अपने बिजली खाते का बैलेंस सकारात्मक रखने की अपील की है। विभाग के अनुसार जिन उपभोक्ताओं का बैलेंस माइनस में होगा, उनकी बिजली आपूर्ति स्वतः बंद हो सकती है। इधर, उपभोक्ताओं के हितों को लेकर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल कर नियमों में संशोधन की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि यदि उपभोक्ता दोबारा रिचार्ज कर अपना बैलेंस प जिटिव कर देता है, तो बिजली आपूर्ति बहाल करने की समय सीमा दो घंटे से घटाकर १० मिनट की जानी चाहिए। परिषद का कहना है कि कई अन्य राज्यों में नियामक आयोग ने यह समय सीमा १५ मिनट निर्धारित कर रखी है, जबकि कुछ राज्यों में यह सीमा १० मिनट है। ऐसे में प्रदेश में भी उपभोक्ताओं को त्वरित राहत देने के लिए इसी तरह का प्रावधान लागू किया जाना चाहिए। परिषद के मुताबिक, प्रदेश में अब तक करीब ७७ लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग ७० लाख मीटर प्रीपेड मोड में काम करना शुरू कर चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार करीब ५० लाख उपभोक्ताओं के बिजली खातों का बैलेंस इस समय माइनस में है, जिससे स्मार्ट मीटरिंग लागू होने के बाद उनकी बिजली कटने की आशंका बनी हुई है। उपभोक्ता परिषद ने यह भी आरोप लगाया है कि बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को पोस्टपेड और प्रीपेड विकल्प चुनने का अधिकार नहीं दे रही हैं। परिषद ने इसे नियमों का उल्लंघन बताते हुए संबंधित बिजली कंपनियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है।

# शिक्षक की पाती अभियान में सैकड़ों शिक्षकों ने भेजे पत्र, उठाई यह मांग

बाराबंकी। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के तत्वाधान में शुक्रवार को विकास खण्ड सिरौलीगौसपुर में "शिक्षक की पाती" अभियान चलाया गया। इस अभियान में सैकड़ों शिक्षकों ने एकजुट होकर लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को टीईटी से मुक्त किए जाने की मांग को लेकर माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा नेता प्रतिपक्ष को पत्र प्रेषित किए। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यह अभियान शिक्षकों की समस्याओं को उच्च स्तर तक पहुंचाने का प्रयास है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकार एवं माननीय न्यायालय शिक्षकों की भावनाओं को समझते हुए इस विषय में सकारात्मक निर्णय लेंगे। अभियान के दौरान शिक्षकों में उत्साह और एकता का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर महासंघ सिरौलीगौसपुर संयोजक रामानंद, डॉ. आशुतोष कुमार, दिलीप तिवारी, रामपाल, अनिल गौतम, राज कुंवर दुबे सहित सुरेंद्र कुमार, आशीष बाजपेई, मनीष बैसवार, नवीन मिश्रा, अपर्णा श्रीवास्तव, अमरदीप सिंह, संजीव मिश्रा, मोहम्मद सुफियान, पूजा जायसवाल और सैंकड़ों अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।

# उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित करेगा : राजनाथ सिंह

लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित करेगा क्योंकि राज्य का ध्यान ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने पर केंद्रित है जिसमें बच्चों का विकास सीखने के सकारात्मक माहौल में हो और वे आगे बढ़ सकें। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में स्थित सिटी मांटेसरी स्कूल गोल्फ सिटी परिसर के मुख्य भवन के उद्घाटन के अवसर पर कहा, श्श्यहां के शिक्षण संस्थान न केवल राज्य के छात्रों के लिए, बल्कि पूरे देश के छात्रों के लिए भी आकर्षण के केंद्र बनकर उभरेंगे।'' उन्होंने कहा कि राज्य का ध्यान केवल स्कूल और क लेज खोलने पर नहीं है बल्कि ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ–साथ सीखने के सकारात्मक माहौल में आगे बढ़ सकें। सिंह ने कहा, ''मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के समन्वित प्रयासों के कारण उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित करेगा।श्श लखनऊ से सांसद सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक व्यापक नजरिए के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, ''हम सभी ने राज्य

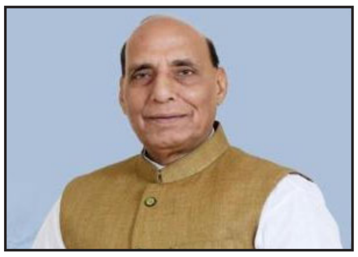

को पिछले कुछ वर्षों में सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति करते देखा है। बुनियादी ढांचे, निवेश, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने नयी गति हासिल की है।श्श उन्होंने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का उल्लेख करते हुए कहा कि इन दूरदर्शी हस्तियों ने समाज के वंचित वर्गों यानी उन लोगों तक शिक्षा पहुंचाई, जो सामाजिक पायदान के सबसे निचले स्तर पर थे। उन्होंने कहा, श्श्उन्होंने यह दिखाया कि समाज में समानता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी साधन है।'' मंत्री ने कहा, ''भारत, अपने नाम के अनुरूप हमेशा ज्ञान की खोज में लगा रहा है। यदि आप इसका इतिहास देखें, तो प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत इस ज्ञान–यात्रा के प्रति दृढ़तापूर्वक समर्पित रहा है।'' उन्होंने कहा कि भारत की ज्ञान परंपराओं में शिक्षा को कभी केवल जानकारी हासिल करने का साधन नहीं माना गया, बल्कि इसे चरित्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण माध्यम समझा गया। उन्होंने कहा कि जब तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय फले–फूले, तब दुनिया के दूर–दराज के हिस्सों से छात्र इन प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए भारत आया करते थे। सिंह ने कहा, ''आपने संभवतः फाह्यान और ह्वेन सांग के नाम सुने होंगे। ये लोग भी भारत आए थे। उन्होंने यह यात्रा इसलिए की क्योंकि इस भूमि में शिक्षा में न केवल ज्ञान प्राप्त करना शामिल है, बल्कि जीवन मूल्यों का समावेश भी शामिल है।''

# लखनऊ में ग्रीन क रिडोर का लोकार्पण : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने जनता को किया समर्पित

लखनऊ। रक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में समता मूलक चौराहे से डालीगंज तक ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने अगले चरण

का शिलान्यास भी किया। शहर के झूलेलाल पार्क में आयोजित समारोह में प्रदेश के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान ग्रीन कॉरिडोर परियोजना को लखनऊ के यातायात को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया। इस परियोजना के माध्यम से शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच आवागमन तेज और सुगम होगा, जिससे ट्रैफिक दबाव कम होने के साथ ही लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। गौरतलब है कि १०० करोड़ की लागत से ग्रीन क रिडोर परियोजना के प्रथम चरण का लोकार्पण ११ मार्च, २०२४ को किया गया था। ६.८ किलोमीटर लंबा ये पुल आईआईएम रोड से पक्का पुल तक बना था जबकि २६६ करोड़ की लागत से आज परियोजना के द्वितीय चरण का लोकार्पण किया गया है। इस चरण के अंतर्गत डालीगंज से लेकर निशातगंज होते हुए समता मूलक चौक तक का हिस्सा आता है। लगभग सात किमी लंबे इस पुल के खुलते ही हजरतगंज, डालीगंज और निशातगंज जैसे घनी आबादी वाले और व्यस्ततम क्षेत्रों में लगने वाले भीषण जाम से बड़ी राहत मिलेगी।

# गाजियाबाद बना आवासीय सौर ऊर्जा का मॉडलः DM ने जारी किया आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले ने आवासीय सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया है। औरैया की पहल से प्रेरित होकर गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब नए बनने वाले आवासीय भवनों के नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में सोलर रूफटॉप सिस्टम

और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस व्यवस्था का उद्देश्य बिजली की बचत के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है। प्रशासन का मानना है कि इससे स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में ऊर्जा संकट से भी राहत मिलेगी। प्रस्ताव के अनुसार नगर निगम, नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें अपने–अपने बोर्ड की बैठकों में प्रस्ताव पारित कर इस व्यवस्था को लागू कर सकती हैं। नक्शा स्वीकृति के बाद भवन निर्माण के दौरान सोलर पैनल और वर्षा जल संचयन प्रणाली का क्रियान्वयन अनिवार्य होगा। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग का दायरा व्यापक होने की उम्मीद है। राज्य सरकार गाजियाबाद की इस पहल को अन्य जिलों के लिए भी अनुकरणीय मान रही है। सरकार का मानना है कि प्रदेश के सभी जनपद स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के स्तर पर नीतिगत निर्णय लेकर आवासीय सोलर कवरेज बढ़ाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश घरेलू रूफटॉप सोलर के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में प्रदेश में कुल १४४० मेगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित की जा चुकी है, जिससे प्रतिदिन ६० लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है। यह बिजली बिना कोयला जलाए उत्पन्न हो रही है, जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों में भी कमी आई है। रूफटॉप सोलर के माध्यम से आम नागरिकों को प्रतिदिन औसतन करीब चार करोड़ रुपये की बिजली बचत का लाभ मिल रहा है। इस पहल से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। लगभग ६० हजार लोगों को प्रत्यक्ष तथा लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही सोलर रूफटॉप मॉडल के कारण ५००० एकड़ से अधिक भूमि का संरक्षण संभव हुआ है, जिसे अन्य विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। सरकार का मानना है कि यदि यह मॉडल प्रदेश के अन्य जनपदों में भी लागू होता है तो उत्तर प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है और हरित भविष्य की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

# अलविदा की नमाज के बाद लखनऊ में प्रदर्शनः अमेरिका-इजराइल के खिलाफ लगे नारे

लखनऊ। रमजान के आखिरी जुमे पर अलविदा की नमाज के बाद शुक्रवार को लखनऊ में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। शहर के कई इलाकों में मस्जिदों के बाहर जमीन पर अमेरिका और इजराइल के झंडे लगाए गए, जिन पर नमाजी आते–जाते समय पैर रखकर गुजरते दिखाई दिए। वहीं शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने आज बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। जिसको देखते हुए प्रशासन ने पुराने लखनऊ सहित संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है और यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुराने शहर में रूट डायवर्जन भी लागू किया गया है। ऐशबाग ईदगाह स्थित जामा मस्जिद में मौलाना खालिद रशीद की इमामत में अलविदा की नमाज अदा की गई। वहीं टीले वाली मस्जिद में भी बड़ी संख्या में नमाजियों ने नमाज पढ़ी। इसके अलावा बड़ा इमामबाड़ा परिसर स्थित आसिफी मस्जिद में शिया समुदाय के लोगों ने अलविदा की नमाज अदा की। नमाज के बाद कुछ स्थानों पर फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन भी हुए।

# ईद उल फितर की नमाज को लेकर अंजुमन कमेटी की बैठक

लखीमपुर खीरी। सिंगाही में मदरसा अंजुमन इस्लामियां में रात को ईद उल फितर की नमाज को लेकर अंजुमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। जिसमें कस्बे की सभी मस्जिदों के इमाम व पदाधिकारी उपस्थित रहे। अंजुमन कमेटी के सिकरेट्री जैनुल हसन ने बताया कि चांद देखने के बाद सुबह ६ बजे ईदगाह पर ईद–उल–फितर की नमाज जामा मस्जिद के इमाम मौलाना शोएब के द्वारा अदा कराई जाएगी। साथ ही जामा मस्जिद में ८ बजे हाफिज अल्वी ईद की नमाज अदा कराएंगे। भरौड़ा की नूरी मस्जिद में ८ ३० पर हाफिज फारुख खां ईद की नमाज मुकम्म करायेंगे। कमेटी के सदर तजम्मुल खान ने कहा कि ईद फितर भाईचारे का प्रतीक है, इसे मिल–जुलकर और शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। किसी भी तरह की अफवाह या गलत सूचना पर ध्यान नहीं दें। उन्होंने लोगों से कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट या वीडियो को न तो शेयर करें और न ही उस पर विश्वास करें। प्रशासन से शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए सुरक्षा को चुस्त बनाने के साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाकर पुलिस का सहयोग करने की बात कही गई। इस दौरान खदीजा मस्जिद के इमाम मौलाना इरफान आयशा मस्जिद के इमाम, मो० तौहीद मौलाना इमामत हुसैन, मो० सफीक, मो० राशिद, मो० शरीफ सहित कई लोग उपस्थित रहे।

# हजरतगंज में एसएमसी अध्यक्ष व सचिवों का प्रशिक्षण, खंड शिक्षा अधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ

लखनऊ। विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता और सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शनिवार को वार्ड संसाधन केंद्र, हजरतगंज में ब्लॉक स्तरीय विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के अध्यक्षों और सचिवों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र जोन–१ द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रशिक्षण सत्र में संदर्भदाता के रूप में सुरेश यादव ने प्रभावशाली तरीके से प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने एसएमसी अध्यक्षों और सचिवों को विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्र–छात्राओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने, विद्यालय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और समुदाय की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर भी मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूलों और समाज के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करती है। यदि समिति के अध्यक्ष और सचिव सक्रिय रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, तो विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अभिभावकों और समुदाय की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के विभिन्न बिंदुओं की व्यवहारिक जानकारी भी दी गई, जिससे वे अपने–अपने विद्यालयों में एसएमसी की भूमिका को और अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकें। प्रशिक्षण में ब्लॉक क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समितियों के अध्यक्ष और सचिव बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और उन्होंने प्रशिक्षण को उपयोगी व मार्गदर्शक बताया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में ब्लॉक क्षेत्र के कई विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समितियों के सदस्य उपस्थित रहे और उन्होंने प्रशिक्षण से संबंधित विषयों पर अपने अनुभव भी साझा किए।

# कोऑपरेटिव बैंक हैकिंग मामले में बड़ी कार्रवाई

लखनऊ। गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट की साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए नाइजीरिया के दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ष्सोलर स्पाइडर' नामक साइबर थ्रेट समूह से जुड़े बताए जा रहे हैं, जो सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा में खामियों का फायदा उठाकर करोड़ों रुपये की अवैध निकासी की योजना बना रहे थे।नाइजीरियाई नागरिकों को साइबर क्राइम थाना, नॉलेज पार्क थाना और मेरठ जोन की साइबर कमांडो टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह सहकारी बैंकों को निशाना बनाता था, जहां साइबर सुरक्षा अपेक्षाकृत कमजोर होती है। आरोपियों की योजना इन बैंकों से करीब ६० से ८० करोड़ रुपये निकालकर उन्हें 'म्यूल अकाउंट्स' में ट्रांसफर करने की थी। इसके बाद यह रकम क्रिप्टोकरेंसी के जरिए विदेश भेजने की तैयारी थी। जांच में यह भी सामने आया कि बीते ७ और ८ मार्च को सप्ताहांत के दौरान आरोपियों ने गुजरात के भावनगर स्थित एक सहकारी बैंक से करीब ७ करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी की थी। बैंक बंद रहने के कारण तुरंत धोखाधड़ी का पता न चल सके, इसलिए यह लेन–देन जानबूझकर सप्ताहांत में किया गया। मामले की गंभीरता को देखते

हुए पुलिस ने तुरंत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और संबंधित बैंकों को अलर्ट किया, जिससे आगे होने वाली करोड़ों रुपये की संभावित धोखाधड़ी को रोका जा सका। जांच में यह भी पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी एक अंतरराष्ट्रीय साइबर नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिसके तार नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय गिरोहों से जुड़े हैं। गौरतलब है कि इसी 'सोलर स्पाइडर' नेटवर्क के एक अन्य मॉड्यूल का भंडाफोड़ गौतमबुद्धनगर पुलिस ने वर्ष २०२५ में भी किया था।

# शिक्षक संघ का अनोखा फरमान, बिना अनुमति स्कूल में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक

बाराबंकी। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ बाराबंकी की ओर से विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के अनधिकृत प्रवेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। संघ के जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय अवधि के दौरान समय–समय पर बाहरी व्यक्तियों का अनधिकृत प्रवेश देखा जाता है, जिससे विद्यालयों के शैक्षणिक वातावरण में व्यवधान उत्पन्न होता है। साथ ही इससे छात्र–छात्राओं और शिक्षकों की सुरक्षा तथा अनुशासन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अनावश्यक प्रवेश से शिक्षण कार्य प्रभावित होता है और विद्यालयों की व्यवस्था बाधित होती है। इसलिए छात्र–छात्राओं एवं शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए जनपद के सभी बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालयों के लिए स्पष्ट

दिशा–निर्देश जारी किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में अनुरोध किया गया है कि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के विद्यालय अवधि में किसी भी बाहरी व्यक्ति का विद्यालय परिसर में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति विद्यालय परिसर में प्रवेश करता पाया जाए तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक एवं विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। संघ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से इस संबंध में आवश्यक आदेश शीघ्र जारी करने की मांग की है, जिससे विद्यालयों में सुरक्षित, अनुशासित और निर्बाध शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर जिला महामंत्री नीरज वर्मा, जिला उपाध्यक्ष विजय सिंह यादव, शैलेन्द्र कुमार, जिला संगठन मंत्री सुधीर चौधरी, विनय शुक्ला, जिला मीडिया प्रभारी सौरभ वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष हरख रवि कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष बनीकोडर चंद्र शेखर सिंह, विशेष कुमार सिंह, आदर्श सिंह सहित अनेक शिक्षक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

# गोला आगमन पर चांदी का मुकुट पहनाकर भाजपा जिलाध्यक्ष का स्वागत

गोला गोकर्णनाथ खीरी। नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता का प्रथम नगर आगमन हुआ। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत करते हुए अभिनंदन किया। नई बाईपास रोड स्थित सनसाइन हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. कौशल वर्मा ने अपनी टीम के साथजिलाध्यक्ष का स्वागत किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर फूल–मालाएं पहनाईं। इस अवसर पर डॉ. कौशल वर्मा ने जिलाध्यक्ष को चांदी का मुकुट पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनके नेतृत्व में संगठन को मजबूत बनाने की बात कही। कार्यक्रम में प्रभात बाजपेयी रुद्र, गोपाल गुप्ता, राजीव पटेल, आनंद वर्मा, ज्ञानचंद वर्मा, कपिल वर्मा, श्रीष्ण वर्मा, विनोद वर्मा, विजय महेश्वरी, संत प्रवीण दास,लालाराम वर्मा, हरिओम कनौजिया, सुरेश कनौजिया (एडवोकेट), अनिल वर्मा, डॉ. सचिन पांडे, अरुण वर्मा, अनुज प्रताप सिंह, अभिषेक वर्मा, विशेष वर्मा, आनंद अर्कवंशी (एडवोकेट), केके वर्मा, सौरभ, आशीष पटेल और आदेश वर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

# सिनेमाघरों में फिर से रिलीज हुई 'धुरंधर'

मुंबई। जियो स्टूडियो और बी–६२ स्टूडियो की सुपरहिट फिल्म 'धुरंधर' अब एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रही है। १६ मार्च को रिलीज होने वाली मोस्टअवेटेड सीक्वल 'धुरंधर द रिवेंज' से ठीक पहले, मूल फिल्म को दुनिया भर

में खास री–रिलीज किया गया है। 'धुरंधर' १२ मार्च से भारत में करीब २५० स्क्रीनों पर और १३ मार्च से विदेशों में लगभग २५० स्क्रीनों पर दोबारा दिखाई जाएगी। कुल मिलाकर दुनिया भर में ५०० स्क्रीनों पर 'धुरंधर' का जादू फिर से देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि उत्तर अमेरिका में ही यह फिल्म १८५ स्क्रीनों पर री–रिलीज हो रही है, जो इसके सीक्वल को लेकर दर्शकों की भारी मांग को दिखाता है। मेकर्स के अनुसार, फैंस के लिए यह सुनहरा मौका है। वे पहले 'धुरंधर' को सिनेमाघरों में दोबारा देख सकेंगे और कुछ ही दिनों बाद उसी कहानी का रोमांचक अगला हिस्सा 'धुरंधर द रिवेंज' भी बड़े पर्दे पर एंजॉय कर पाएंगे। हिंदी फिल्मों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर री–रिलीज बहुत कम होती है, ऐसे में यह कदम फ्रेंचाइजी की वैश्विक लोकप्रियता को दिखाता है। वहीं, 'धुरंधर द रिवेंज' के स्पेशल प्रीमियर शो १८ मार्च को अमेरिका और कनाडा में आयोजित होंगे। ये शो ज्यादातर प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट (पीएलएफ) स्क्रीन्स पर होंगे, जहां बड़ी स्क्रीन, डॉल्बी एटम स साउंड, बेहतर प्रोजेक्शन और लग्जरी सीटिंग मिलेगी। ऐसे फॉर्मेट आमतौर पर बड़े हॉलीवुड इवेंट फिल्मों के लिए इस्तेमाल होते हैं। कई प्रीमियर शो के टिकट पहले ही हाउसफुल हो चुके हैं। हाल ही में रिलीज 'धुरंधर द रिवेंज' के ट्रेलर को दुनियाभर के दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है। ट्रेड एक्सपर्ट्स और सिनेमाघर मालिक इसकी अंतरराष्ट्रीय रिलीज से बड़ी उम्मीदें लगा रहे हैं। 'धुरंधर द रिवेंज' जियो स्टूडियोज की प्रस्तुति और बी ६२ स्टूडियोज का प्रोडक्शन है। यह हाई ऑक्टेन स्पाई एक्शन थ्रिलर आदित्यधर ने लिखी और निर्देशित की है। ज्योति देशपांडे और लोकेशधर भी इसके निर्माता हैं। फिल्म १६ मार्च को गुड़ी पड़वा और उगादी के मौके पर हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ में दुनियाभर में रिलीज होगी।

# कोई नौकरी नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए क्यों कही ये बात?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महिला छात्रों और कामकाजी पेशेवरों को मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाली एक समान राष्ट्रीय नीति की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के लाभ को अनिवार्य बनाने से अनजाने में रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिल सकता है और नियोक्ताओं को महिलाओं को नौकरी पर रखने से रोका जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ज यमाल्य बागची की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस अनुरोध का महिलाओं के रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। याचिकाकर्ता की दलील पर सुनवाई करते हुए पीठ ने टिप्पणी की, ये दलीलें भय पैदा करने, महिलाओं को हीन बताने और यह जताने के लिए दी जा रही हैं कि मासिक धर्म उनके लिए कोई बुरी घटना है। यह एक सकारात्मक अधिकार है। लेकिन उस नियोक्ता के बारे में सोचिए जिसे सवैतनिक अवकाश देना पड़ता है। न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि मासिक धर्म अवकाश एक वैध मुद्दे को

स्वीकार करता है, लेकिन इसे कानून के माध्यम से अनिवार्य बनाना सामाजिक और व्यावसायिक रूप से प्रतिकूल हो सकता है। यह जनहित याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर की गई थी, जिनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद ने बताया कि कुछ राज्यों और निजी संगठनों ने पहले ही मासिक धर्म अवकाश लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि केरल ने छात्रों को छूट दी है और कई कंपनियों ने स्वेच्छा से ऐसा अवकाश प्रदान किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्वैच्छिक उपाय स्वागत योग्य हैं, लेकिन उन्होंने कानूनी बाध्यता के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक रूप से दिया गया अवकाश उत्कृष्ट है। जिस क्षण आप इसे कानून में अनिवार्य कर देंगे, कोई भी उन्हें नौकरी नहीं देगा। कोई भी उन्हें न्यायपालिका या सरकारी नौकरी में नहीं लेगाय उनका करियर खत्म हो जाएगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने के कारण वह परमादेश जारी करने के लिए इच्छुक नहीं है। पीठ ने संबंधित अधिकारियों को सभी हितधारकों से परामर्श करके प्रस्ताव का मूल्यांकन करने और उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया। तदनुसार, जनहित याचिका का निपटारा कर दिया गया।

# एलपीजी संकट पर अखिलेश का केंद्र पर हमला

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने एलपीजी संकट पर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गैस लापता हो गई। उन्होंने कहा कि अगर कोई अफवाह फैला रहा है, तो वह सरकार है। अगर सरकार यह मान ले कि गैस की कमी है, तो जनता भी सहयोग करेगी, लेकिन सरकार का दावा है कि कहीं कोई कमी नहीं है और गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि हकीकत यह है कि गैस तो जैसे गायब ही हो गई है। हर शहर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी में सिलेंडरों के लिए लंबी–लंबी कतारें लगी हैं। शायद ही कोई ऐसा जिला बचा हो, जहां लोग लंबी लाइनों में खड़े न हों। आखिरकार इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। अफवाह सरकार ने फैलाई कि इतने दिन बाद बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन में बुकिंग के दौरान दिक्कत है, ऑनलाइन गैस बुक नहीं कर सकते। अखिलेश यादव ने कहा कि यह दौर सोशल मीडिया का है, संकट को आप छिपा नहीं सकते। गैस संकट की वजह से रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। लोगों की शादियां रुक रही हैं। अगर दिक्कत ज्यादा बढ़ी तो लोग खाना कैसे बनाएंगे। रेहड़ी–पटरी वाले कैसे काम करेंगे। चाट वाले अब चाट भी नहीं बना पाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के नोटिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम और हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है, क्योंकि चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुन रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारे कैमरों ने वह सब रिकॉर्ड

किया है जो कुछ भी हुआ। उपचुनाव को लूट लिया गया। उस समय चुनाव आयोग क्या कर रहा था। हम लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। जम्मू–कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला एक वरिष्ठ नेता हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर दोहराता हूं कि सरकार को उनकी उचित और पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। वह एक महत्वपूर्ण नेता हैं जो समाज में अहम योगदान दे सकते हैं और देश को सही दिशा दिखाने में मदद कर सकते हैं। उनकी सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

# 'सुर साधना' से गूंज रही यूपी की लोक संस्कृति, २२०० से अधिक कलाकारों को मिला मंच

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि राज्य की लोक कला और परंपराएं हमारी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत की मजबूत

नींव हैं। श्सुर साधनाश जैसे आयोजन इन परंपराओं को नया जीवन देने का कार्य कर रहे हैं। २२ जिलों में चल रही 'सुर साधना' में अब तक ३७४ सांस्कृतिक दलों के करीब २२०० से अधिक कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। १५६ दिनों में आयोजित इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को नया मंच मिल रहा है। इन कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न जिलों के धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों पर किया जा रहा है, जहां स्थानीय कलाकार लोकगायन, भजन–कीर्तन, लोकनृत्य, लोकनाट्य, कठपुतली और जादू जैसी विधाओं की प्रस्तुति दे रहे हैं। इसके साथ ही शास्त्रीय गायन–वादन, किस्सागोई और काव्य पाठ भी कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जिससे दर्शकों को प्रदेश की विविध लोक कलाओं से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। 'सुर साधना' कार्यक्रम में कलाकारों को उनकी प्रस्तुति के अनुसार सम्मानजनक मानदेय भी दिया जा रहा है। लोक नृत्य के लिए १५ हजार रुपये, लोक भजन गायन के लिए १० हजार रुपये और अन्य विधाओं जैसे जादू, कठपुतली, किस्सागोई/दास्तानगोई तथा काव्य पाठ के लिए ५ हजार रुपये मानदेय निर्धारित किया गया है। जयवीर सिंह ने कहा कि इस पहल के माध्यम से प्रदेश के लोक कलाकारों को मंच मिल रहा है और लोगों को भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के हर क्षेत्र में मौजूद कलाकारों को मंच मिले और लोक संस्कृति नई पीढ़ी तक पहुंचे, ताकि परंपराएं निरंतर जीवंत बनी रहें।

# श्री चण्डी महायज्ञ एवं विशाल संत समागम धूमधाम से संपन्न हुआ

लखीमपुर–खीरी। सेनाताल भंसडिया स्थित दुर्गा मां स्थान पर आयोजित प्रथम पंचदिवसीय श्री चण्डी महायज्ञ एवं विशाल संत समागम कार्यक्रम ८ मार्च से १२ मार्च तक अत्यंत भक्ति भाव एवं उत्साह के साथ संपन्न हुआ। यह धार्मिक आयोजन पूरे क्षेत्र में भक्ति की लहर लेकर आया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आयोजन के मुख्य आयोजक आचार्य पंडित शिवसरन मिश्रा जी महाराज, नई बस्ती, भंसडिया संरक्षक श्री दुर्गा भगवती मां के आशीर्वाद से पूरा कार्यक्रम संचालित हुआ। मुख्य यजमान के रूप में विष्णु मिश्रा एवं कमल किशोर तिवारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान राम किशोर वर्मा, सोनू तिवारी व संपूर्ण ग्रामवासी, क्षेत्रवासी एवं सहयोगी समिति के सदस्यों के अथक प्रयासों से यह यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पांच दिनों तक चले इस महायज्ञ में मां दुर्गा की आराधना, चण्डी पाठ, हवन, कीर्तन एवं प्रवचनों का क्रम चलता रहा। पूरा वातावरण भक्ति रस से ओतप्रोत हो गया। बच्चे, युवा, महिलाएं एवं बुजुर्ग सभी ने मिलकर कार्यक्रम में भाग लिया और इसका भरपूर आनंद उठाया। संत समागम में विभिन्न संतों–महात्माओं के सान्निध्य से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हुई। कार्यक्रम के समापन अवसर पर सदर विधायक योगेश वर्मा विशेष रूप से पहुंचे। उन्होंने यज्ञ स्थल पर मां दुर्गा के दर्शन किए, भण्डारा प्रसाद ग्रहण किया तथा आयोजकों एवं श्रद्धालुओं को बधाई दी। विधायक ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में एकता, भक्ति एवं सद्भावना को मजबूत करते हैं।

# शांति से संपन्न हुई जुम्मे की नमाज प्रशासनिक अधिकारी रहे मुस्तैद

धौरहरा खीरी। रमजान माह के होने वाले आखिरी शुक्रवार (जुमे)को क्षेत्र में अलविदा की नमाज शान्ति से सकुशल संपन्न हो गई। अलविदा की नमाज के लिए पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अफसरों की क्षेत्र में मौजूदगी की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम समुदाय का पवित्र महीना रमजान के आखिरी शुक्रवार जुमे की नमाज व सकुशल व शान्ति से निपटाने के लिए एसडीएम धौरहरा शशीकांत मणि व क्षेत्राधिकारी धौरहरा शमशेर बहादुर सिंह के पर्यवेक्षण में तहसीलदार धौरहरा आदित्य विशाल, नायब तहसीलदार फिरोजाबाद अखिलेश मौर्या,नायब तहसीलदार धौरहरा बीरेंद्र

यादव,थाना प्रभारी खमरिया ओ पी राय,ईसानगर निर्मल तिवारी, धौरहरा रविन्द्र सोनकर,पढ़ुवा विवेक कुमार उपाध्याय, शारदानगर मनोज कुमार सिंह उप निरीक्षको व बीट कांस्टेबलो,समस्त राजस्व निरीक्षक, संबंधित लेखपालों को अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद रहकर क्षेत्रीय गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था। समाचार प्रेषण तक क्षेत्र में अलविदा की नमाज मस्जिदों में शान्ति पूर्ण सम्पन्न हो गई।इस दौरान एसडीएम धौरहरा शशीकांत मणि ने कहा कि अलविदा की नमाज क्षेत्र में सकुशल संपन्न हुई।

# आतंकवाद का निर्णायक जवाब देने में देश पूरी तरह सक्षम : राजनाथ सिंह

लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ कड़ा और निर्णायक जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका निर्माण अब लखनऊ में भी किया जा रहा है जो देश की सैन्य शक्ति को और मजबूत बना रहा है। रक्षामंत्री ने लखनऊ के झूलेलाल वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब भारत पर हमला करना आसान नहीं है। यदि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो उन्हें इतना कड़ा जवाब मिलेगा कि वे भारत पर हमला करने से पहले सौ बार सोचेंगे। भारत के जवाबी हमले इतने प्रभावी होंगे कि आतंकवादी उससे कभी उबर नहीं पाएंगे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का

भी जिक्र किया। उन्होंने घोषणा की कि लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण अगले माह किया जाएगा, जिससे दोनों शहरों के बीच आवागमन और तेज व सुगम होगा। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर और जापान यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि शुरुआत में उन्हें आशंका थी कि मुख्यमंत्री की यह यात्रा कहीं स्थगित न हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने विदेश दौरा किया और भारतीय वेशभूषा तथा खान–पान के साथ प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आया है। रक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में सड़क अवसंरचना को और मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। लखनऊ –सीतापुर हाईवे को सिक्स लेन किए जाने की दिशा में कार्य जारी है, वहीं उसके अपग्रेडेशन की भी योजना है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग को आगे चलकर लखनऊ –वाराणसी क रिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे प्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच संपर्क और बेहतर होगा।

# प्रेमिका के खातिर ले ली दोस्त की जान, हत्या की वजह पुलिस भी हैरान

एटा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक द्वारा अपने ही दोस्त की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी मोहित और उसके भाई रवि को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार थाना निधौली कला क्षेत्र के मितरोल गांव निवासी मोहित (१६) पड़ोस की एक युवती से प्रेम करता था। कुछ समय पहले उसे पता चला कि उसका दोस्त धर्मेन्द्र (१७) भी उसी युवती से बातचीत कर रहा है। इसी बात को लेकर मोहित ने धर्मेन्द्र से रंजिश पाल ली और उसे रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। योजना के तहत मोहित ने घटना से करीब १२ दिन पहले बाजार से कुल्हाड़ी और रस्सी खरीदी तथा उसे घटना स्थल के पास खेत में छिपा दिया। छह फरवरी की सुबह करीब साढ़े तीन बजे उसने अपने भाई के फोन से धर्मेन्द्र को दौड़ लगाने के बहाने बुलाया। दौड़ के दौरान मोहित ने भर्ती की ट्रेनिंग का बहाना बनाकर रस्सी से धर्मेन्द्र के पैर बांध दिए और उसे सरसों के खेत में ले जाकर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, मृतक का मोबाइल और जले हुए कपड़ों की राख बरामद कर ली है।

# मलाइका अरोड़ा ने लॉन्च किया नया लाइफस्टाइल ब्रांड 'मेजॉय'

मुम्बई। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने अब फैशन बिजनेस में भी बड़ा कदम रखा है। उन्होंने एक नया लाइफस्टाइल एक्सेसरी ब्रांड ल न्च किया है, जिसका नाम 'मेज य' रखा गया है। यह ब्रांड उन्होंने एक्सीड एंटरटेनमेंट और मिंत्रा की बी२बी होलसेल कंपनी 'मिंत्रा जबोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' (एमजेआईपीएल) के साथ मिलकर तैयार किया है। मेज य ब्रांड की शुरुआत एक बड़े कलेक्शन के साथ की गई है। इसके पहले कलेक्शन में २५० से ज्यादा अलग–अलग डिजाइन शामिल किए गए हैं। इस कलेक्शन में खास तौर पर दो तरह की एक्सेसरी पर ध्यान दिया गया है, पहला हैंडबैग और दूसरा लैब–ग्रोन डायमंड ज्वेलरी। हैंडबैग के कई स्टाइल इस कलेक्शन में देखने को मिलते हैं, जैसे क्र सब डी बैग, स्ट्रक्चर्ड शोल्डर बैग, बकेट बैग, टोट बैग, अ फिस के लिए क्लासिक बैग, बैकपैक और क्लच। इन बैग्स को अलग–अलग तरह के मटेरियल से बनाया गया है, जिनमें सिंथेटिक लेदर, ब्रेडेड डिजाइन, साटन, राइनस्टोन और मेटैलिक फिनिश जैसे मटीरियल शामिल है। हर बैग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह फैशनेबल भी लगे और रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी आरामदायक हो। हैंडबैग के अलावा इस ब्रांड में लैब–ग्रोन डायमंड ज्वेलरी का भी खास कलेक्शन पेश किया गया है। इसमें रिंग, इयररिंग, पेंडेंट, ब्रेसलेट और टेनिस ब्रेसलेट जैसे कई डिजाइन शामिल हैं। इन ज्वेलरी पीस को सिल्वर, गोल्ड और रोज–गोल्ड टोन में तैयार किया गया है। इनका बेस ६२५ स्टर्लिंग सिल्वर से बनाया गया है, जो ज्वेलरी की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। इसके साथ ही इन ज्वेलरी में इस्तेमाल किए गए डायमंड को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं आईजीआई और जीसीआई से प्रमाणित किया गया है। मेज य सिर्फ एक फैशन ब्रांड नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक

खास सोच भी है। इस ब्रांड का मुख्य संदेश है 'द जॉय ऑफ बीइंग मी', यानी अपने असली रूप में खुश रहना। ब्रांड तीन मुख्य सिद्धांतों पर काम करता है– असलीपन, आत्मविश्वास और आसानी से उपलब्ध होना। इसके लिए वह ऐसे डिजाइन पेश करना चाहता है जो स्टाइलिश और एस्पिरेशनल हों, लेकिन साथ ही इतने सुलभ हों कि लोग उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ब्रांड के लॉन्च के मौके पर मलाइका अरोड़ा ने कहा मेजॉय मेरा एक ऐसा सपना है जिसे मैंने लंबे समय से संजोकर रखा था। अपने पूरे करियर में मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि फैशन लोगों को आत्मविश्वास दे और उन्हें सहज महसूस कराए। 'दॉज य ऑफ बीइंग मी' खुद का जश्न है, ताकि हर महिला अपनी पहचान को गर्व के साथ स्वीकार करे और अपने स्टाइल के जरिए उसे दुनिया के सामने रखे। इस ब्रांड के जरिए मैं ग्लोबल फैशन ट्रेंड्स को आम महिलाओं तक पहुंचाना चाहती हूं ताकि हर महिला रोजमर्रा की जिंदगी में भी थोड़ी–सी लग्जरी का अनुभव कर सके, चाहे वह एक खूबसूरत हैंडबैग हो या एक आकर्षक डायमंड ज्वेलरी पीस। इस मौके पर एमजेआईपीएल के हाउस अ फ ब्रांड्स के प्रमुख सुमन साहा ने भी मेज य को लेकर अपनी राय साझा की। उन्होंने कहा यह ब्रांड मलाइका अरोड़ा के खास फैशन सेंस और म र्डन स्टाइल को लोगों तक पहुंचाने का एक शानदार प्रयास है। यह ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो ट्रेंडी और स्टाइलिश एक्सेसरी पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही चाहते हैं कि वे चीजें उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के साथ भी मेल खाएं। इस ब्रांड के नए और आकर्षक डिजाइन ग्राहकों को जरूर पसंद आएंगे और यह ब्रांड फैशन एक्सेसरी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाएगा। वहीं एक्सीड एंटरटेनमेंट के सीईओ अफसर जैदी ने कहा किसी सेलिब्रिटी के साथ मिलकर ब्रांड बनाना एक जिम्मेदारी भरा काम होता है। इसमें उस कलाकार की असली पहचान और बाजार की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी होता है। हमारी कंपनी पहले भी मिंत्रा के साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है, इसलिए मेज य को ल न्च करने की प्रक्रिया काफी सहज रही। मलाइका अरोड़ा फैशन की दुनिया में आइकन मानी जाती हैं और वह बिजनेस को भी अच्छी तरह समझती हैं। मेज य ब्रांड के प्रोडक्ट्स फिलहाल अ नलाइन उपलब्ध हैं, और ग्राहक उन्हें सीधे मिंत्रा की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए खरीद सकते हैं।

# कक्षा अष्टम का विदाई समारोह संपन्न

लखीमपुर–खीरी। विद्या भारती विद्यालय बराती लाल गोमती देवी सरस्वती विद्या मंदिर मितौली खीरी में कक्षा अष्टम का विदाई समारोह संपन्न हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य सुधाकर मिश्रा ने मां सरस्वती जी पूजन अर्चन कर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। प्रधानाचार्य ने भैया बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह मात्र विदाई नहीं उच्च शिक्षा के लिए प्रस्थान है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है, शिक्षा के साथ संस्कार का बहुत ही बड़ा महत्व है किताबी ज्ञान से ही बच्चों की शिक्षा पूर्ण नहीं होती है इसके लिए बच्चों को संस्कार वान बनाना पड़ता है जिससे बच्चों का ही नहीं देश का निर्माण होता है इन्हीं बच्चों पर हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है। अभिभावकों को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा विद्यालय से आने के बाद क्या करता है ये सभी अभिभावकों का दायित्व है। विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य पंकज दीक्षित ने कार्यक्रम का कुशल संचालन किया। इस अवसर पर नितेश, जितेंद्र जी, उपेन्द्र जी, महेंद्र जी, देवेश जी, हर्षित जी आचार्य आचार्या बहने एवं भैया बहन उपस्थित रहे प्रधानाचार्य सुधाकर मिश्र ने सभी का आभार व्यक्त किया और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की।

हमारे अन्य प्रतिनिधि
संजय बाजपेई
सीतापुर
मो.9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
सुरेश नारायण मिश्र
क्षेत्रीय सम्पादक
सौरभ कुमार, बिहार
मो.09386075289
मो० अरशद
ब्यूरो चीफ
मऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई
UPHIN/2010/32566

सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178
Email-
adbhutsamachar@yahoo.in
adbhut_samachar@rediffmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक